THE DEPUTY CHAIRMAN: Let the Government decide...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is not a private affair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know that. You please sit down... You see the Minister is ready to enquire. Now let the Government decide what type of enquiry, in what manner and at what level it is going to take place... It takes time. Let her come out; as soon as it is decided, with a statement. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: How long will it take to announce it?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Since the matter is *sub judice*. ...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: But how long will they take?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't argue with the Chair. You cannot do like that. I have said that she is going to enquire into it and come before the House.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Is it a Five Year Plan? The man has died. How long will the Government take?

THE DEPUTY CHAIRMAN: As soon as it is complete.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: She should have been prepared to make a statement today.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't argue with the Chair, Mr. Dasgupta. This is not the way. You sit down.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: She should have been ready to make a statement today.

KUMARI SAROJ KHAPARDE: I would like to submit humbly, Madam after lunch hour; if you permit me...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will always permit.

KUMARI SAROJ KHAPARDE: ... I would like to come here and make a *suo motu* statement in the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Minister of Agriculture to make a statement regarding procurement/minimum support prices for paddy, kharif cereals etc. for 1988-89 season.

STATEMENTS BY MINISTERS

I. Procurement/Minimum Support Price for Paddy, Kharif Coarse Cereals; Kharif Pulses Kharif Oilseeds and Raw Cotton for 1988-89 Season

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): महोदया, सरकार ने 1988–89 मौसम के लिये धान, खरीफ के मोटे अनाजों, खरीफ दालों, खरीफ तिलहनों और कपास के वसूली मूल्य निर्धारित कर दिये हैं। बढ़िया औसत श्रेणी के सामान्य समूह में धान की सभी किस्मों का वसूली मूल्य 1987–88 विपणन मौसम में 150 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1988–89 विपणन मौसम में 160 रु० प्रति क्विंटल कर दिया है।

1988–89 मौसम के लिये धान की बढ़िया किस्म का मूल्य 170 रु० प्रति क्विंटल और धान की सबसे बढ़िया किस्म का 180 रु० प्रति क्विंटल होगा जो कि 154 से 170 और 158 से 180 रु० किया गया है।

सरकार ने खरीफ के मोटे अनाजों यानी ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी की अच्छी औसत श्रेणी का वसूली मूल्य 1988–89 मौसम के लिये 145 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जो कि 1987–88 मौसम के लिये निर्धारित किया है 135 रु० प्रति क्विंटल से 10 रु० प्रति क्विंटल अधिक है।

सरकार की कोशिश रही है कि दालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। तदनुसार, 1988–89 फसल की खरीफ

दालों यानी तुर (अरहर) उड़द और मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य 360 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किये गये हैं जो कि 1987-88 फसल के उत्पाद के मूल्य की तुलना में 35 रु० प्रति क्विंटल अधिक है।

भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) को राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सहकारी विपणन एजेंसियों के सहयोग से 1988-89 मौसम की खरीफ दालों की खरीद करने के लिये ग्रंथिल एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है।

तिलहनों के उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को भी काफी बढ़ा दिया हैं। तदनुसार, 1988-89 फसल की छिलके-सहित मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 430 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो कि पिछले वर्ष के मूल्य की अपेक्षा 40 रु० प्रति क्विंटल अधिक है।

1988-89 फसल के सोयाबीन (पीला) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 320 रु० प्रति क्विंटल होगा जो कि पिछले वर्ष 300 रु० प्रति क्विंटल था। इसी प्रकार 1988-89 मौसम के लिये सोयाबीन (काला) का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 15 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि करके 275 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया गया है। इसी तरह, 1988-89 मौसम के लिये उभरती हुयी तिलहन सफल सूरजमुखी बीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 60 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि करके 450 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया गया है।

कपास के लम्बे और बढ़िया रेशा समूह में बेसिक किस्म एच-4 का न्यूनतम समर्थन मूल्य 600 रु० प्रति क्विंटल होगा जो कि पिछले मौसम की तुलना में 50 रु० अधिक होगा। एफ-414/ एच-777 किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रु० प्रति क्विंटल होगा। यह मूल्य पिछले मौसम के मूट की तुलना में न केवल 60 रु० प्रति क्विंटलल्यअधिक होगा बल्कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सुझाए गये मूल्य से भी 15 रु० प्रति क्विंटल अधिक होगा। यह इसलिये किया गया है कि उप-जातीय असंतुलन, विशेषत: कपास की मध्यम रेशे वाली किस्मों की मांग और आपूर्ति में, को दूर किया जाये तथा कपास और कपास के धागों के निर्यातकों को पर्याप्त कपास उपलब्ध कराई जाए।

यदि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरते हैं तो भारतीय कपास निगम सभी कपास उत्पादक राज्यों में मूल्य समर्थन कार्यों को करेगा, महाराष्ट्र इसका अपवाद होगा।

मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा वसूली न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि द्वारा दिये गये प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप खाद्य फसलों के साथ-साथ तिलहनों और कपास की उत्पादकता और उत्पादन में वांछित वृद्धि को प्राप्त करने के लिये हमारे किसानों को प्रेरणा मिलेगी।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairperson, while welcoming the statement made by the honourable Minister; I would like to draw the attention of the House to the price as far as cotton is concerned. It appears that the Government did not take into consideration the price of cotton in relation to the price of cloth. As far as the long staple and extra-long staple cotton that is produced in Guntur and Prakasam districts is concerned, the price is fixed only at five rupees per kilogram. Madam three kilograms of cotton yield two kilograms of seed and one kilogram of lint and that one kilogram of lint produces eight metres of cloth and the same cloth that is produced from this variety of cotton costs Rs. 20 per metre. So, out of these Rs. 160—the cost of eight metres of cloth—only Rs. 15 is going to the farmer. It appears that there is no rationale between the cost of cloth and the cost of cotton. Madam, through you I would like to draw the Government's attention to this and ask

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

whether there is any rationale between the price of cloth and the price of cotton. On the other hand, for the last ten years or fifteen years the cotton growers of Prakasam and Guntur districts are producing extra-long staple cotton which was much superior to be best quality Egyptian cotton. Will the Minister increase further the price of cotton as incentive to the cotton growers?

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने किसानों के लिये कुछ मूल्य बढ़ाये हैं इसके लिये मैं उनका हृदय से आभार मानता हूं। इसके लिये सारा सदन और सारे देश के किसान उनके आभारी हैं। लेकिन महोदया, मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि एक तो आपकी इस घोषणा में यह नहीं है कि जहां बारिश नहीं हुयी तो सूखा राहत कार्यों में, खासकर जो बीमे का मामला है उसको और स्पष्ट करें कि इस बीमे का जो उपयोग है वह ग्रामीण स्तर पर किया जायेगा या नहीं किया जायेगा ?

उपसभापति : यह अभी रिप्लाई में आ जायेगा।

श्री भजन लाल : यह मैं अपने रिप्लाई में बता दूंगा।

श्री राम चन्द्र विकल : दूसरा, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो कृषि लागत मूल्य आयोग है जिसके कारण आपकी यह घोषणा है उसका गठन अभी हुआ है या नहीं हुआ है ?

श्री भजन लाल : यह भी बता दूंगा। आपने यह सवाल कल भी उठाया है, मैं अभी अपने जवाब में बहुत सी बातें बताऊंगा।

श्री राम चन्द्र विकल : फिर आप मौका देंगे स्पष्टीकरण का ?

आप हृदय से बधाई के पात्र हैं जो आपने किसानों की तरफ ध्यान दिया। मैं इसके लिये पुनः आपको बधाई देता हूं।

श्री वीरेंद्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीया, मैं माननीय कृषि मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं और इसके लिये कृषि मंत्री को बधाई देता हूं जो उन्होंने किसानों की उचित मांगों की ओर ध्यान दिया है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये प्राइस किसानों को मिलेंगीं या नहीं जो उन्होंने निर्धारित की हैं ? क्योंकि समय पर क्रय केन्द्र न खोले जाने के कारण काश्तकार मजबूर हो जाते हैं और वे डिस्ट्रेस सेल करते हैं। यह कीमतें जो आपने मुकर्रर की हैं चाहे उनसे एफ० सी० आई० खरीद करे चाहे नाफेड खरीद करे और चाहे कोई भी खरीद करे, मान्यवर, आप मेरे से सहमत होंगे कि आजकल सरसों बाजार में आ रही है। जब सरसों बाजार में आने लगती है तो उसके भाव बहुत गिर जाते हैं और व्यापारी किसानों से उसको खरीद लेते हैं और बाद में उसी सरसों को व्यापारी दुगुने भाव पर बेंचते हैं। ... (**व्यवधान**) ... इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन भावों को सुनिश्चित करने के लिये किसानों को क्रय केन्द्र समय से मिलें इसके लिये वे क्या-क्या व्यवस्था करेंगे ? जब मंत्री महोदय अपना उत्तर दें तो वे इस पर अवश्य प्रकाश डालें। धन्यवाद।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, I am happy that the Minister has increased the support prices of agricultural commodities. But he has not taken into account the real picture of today regarding the products manufactured from these items. You have increased by 10 per cent the price of oil seeds. But the price of edible oil, groundnut oil has gone up by 30 per cent in the last one year. Similarly, the price of tur dal has gone up by 30 per cent. But here you have given an increase of only 10 per cent. So, you have to take the real picture of the whole situation, and you must increase the prices taking into account the present day situation of the manufactured items. Otherwise the farmers will not get the advantage. It is only the

business community which will get it. They will buy them now and after six or seven months they will sell them by a profit margin of more than 100 per cent. That is why, if you really want that the farmers should benefit then, you must increase the support prices substantially. You must take into account the present picture. I feel very strongly that you must come up with a proposal for increasing the support prices by 20 per cent. Then only they will reflect the present situation. Otherwise, the farmers will not get the benefit.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, it is good that the Government is sheding tears for the farmers. But they are only crocodile tears because the price rise that the Government has announced is absolutely inadequate and absolutely marginal because if the Minister goes into the price movement of the agricultural products and industrial products he will definitely come to the conclusion as it has been done by all the economists of this country that there is great imbalance in favour of the industry. The farmers are being deprived of crores of rupees because of unremunerative prices because of distress sale. That is the situation in the country. That imbalance has not been corrected by the marginal, inadequate step that the Government has proposed to take. Therefore, I call it crocodile tears.

The second point on which I would like a clarification from the Minister is that there is a complaint about the purchase machinery that the Government sets up to mop up the purchase in the open market; about the F.C.I. In the beginning of the season, the F.C.I. does not go into action. Therefore distress sale takes place and even when it purchases; on account of weight on account of variety on account of gradation; the poor; uneducated; peasants are cheated. Therefore, what steps are you going to take to ensure that the F.C.I., by making such purchases, does not cheat the peasantry?

My third point is, is the Minister aware that there has been an increasing number of suicides among the cotton-growers in Andhra Padesh the reason being that they have taken loans from banks and the price generally fetched in the open market is too short to cope with the expenses? In his statement, the Minister has said that the Cotton Corporation of India will undertake price support operations. (*Interruptions*) My point is to what extent the Cotton Corporation of India will undertake the operations? Will it be ready to purchase all that is offered for sale by the farmers? I would like to know the extent of the open market operation by the Cotton Corporation of India, particularly in Andhra Pradesh; in view of the distress sale, in view of the increasing number of suicides.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय को सब से पहले बधाई देता हूं। जैसे मैं ने सोचा था वैसा ही हुआ है क्योंकि मन्त्री महोदय ने अपनी मिनिस्ट्री का चार्ज लेते ही 10 लाख ट्यूबवेल्ज़ लगाने की घोषणा की और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसानों की फसल के दाम बढ़ाये गये हैं इसलिये मैं मंत्री महोदय को अपनी तरफ से और भारत के सारे किसानों की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने 10 रु0 से 50 रुपये तक दाम बढ़ाये हैं आयल सीड्ज का 40 रुपये बढ़ाया है और यह जो काटन कारपोरेशन है उन्होंने एश्योरेंस दिया है, महाराष्ट्र को छोड़ कर जहां काटन फेडरेशन स्कीम है वह अपनी जगह है, कि इफेक्टिवली उसका काम करायेंगे मैं मन्त्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जो काटन मोनोपोली स्कीम है जो वह बहुत सी ही अच्छी तरह से चल रही है इफेक्टिवली चल रही है। किसानों की जो आर्थिक अवस्था है और उनके माल की जो खरीद होती है जब तक कि किसानों की आर्गेनाइजेशन नहीं होगी तब तक उनको किसी भी प्रकार से न्याय नहीं मिल सकता है।

[श्री विट्ठलराव माध वराव जाधव]

हमारे मंत्री महोदय डायनेमिक हैं इसलिये इस में काफी सुधार करेंगे । मैं यह कृषि मंत्रालय के लिये अहम सवाल उठा रहा हूं । जैसे महाराष्ट्र की धरती पर कॉटन मोनोपो ी स्कीम है क्या इस सारे भारत में सरकार करने जा रही है या नहीं? दूसरा मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने काटन मोनोपोली स्कीम की 10 साल की परमिशन मांगी हैं उसके बारे में सरकार अच्छी तरह से सोच रही है तो उसका जबाब दे तथा यह जो स्कीम उन्होंने लागू की है मेरे दिल में कोई शक नहीं कि मंत्री महोदय बत इफेक्टिवली और अच्छी तरह से किसानों को मदद देंगे । इसलिये मैं फिर एक बार मन्त्री महोदय को पधाई देता हूं ।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो बयान अभी किसान के उत्पादन के मूल्यों के सबंध में दिया है देश की जनता ऐसा समझती थी कि शायद कृषि मंत्री जी कोई ऐसा मूल्य बढ़ा कर के किसानों को देंगे जिससे उनके मन में एक आशा का संचार होगा लेकिन जो वक्तव्य आया है उससे देश के किसानों को बड़ी निराशा हुयी है । यह निराशा इसलिये हुई हैं हमारे देश में बहुत से कृषि विश्व-विद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों ने भी समय समय पर उसके मूल्य निकालने का काम किया है लेकिन भारत सरकार ने अगर उन मूल्यों पर ध्यान दिया होता तो शायद इस तरह इन किसानों के साथ अन्याय नहीं होता । जो लाभकारी मूल्य किसानों को मिलने चाहिये वे नहीं मिल पाये । केवल धान में 10 रु० बढ़ा कर और फिर कुछ अन्य सामानों के दाम बढ़ा कर सरकार ने कुछ नहीं दिया है । किसानों का बिजली का रेट बढ़ गया है खाद के दाम बढ़ गये हैं और कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़े हैं, मजदूरी बढ़ी है । सारी चीजों के दाम बढ़े हैं उसे सरकार ने ध्यान में नहीं रखा है । अगर ध्यान में रखा होता तो सम्भवत: देश के किसानों को कुछ लाभ मिला होता । इसलिये इस बयान से महोदया, बहुत ही निराशा हाथ लगी है और सरकार से मेरी मांग है कि सरकार इस दिशा में सोचे । अगर अपने को किसानों का हितैषी होना सरकार बताती है माननीय कृषि मंत्री बतात हैं तो निश्चित रूप से धान के दाम 160 रुपये प्रति क्विंटल रखने का जो काम किया है उसे बढ़ाकर कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल कीजिये । इसी तरह से और भी चीजों के दाम बढ़ाने चाहिये । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दाम तो सरकार तय कर देती है लेकिन कहीं पर भी खरीद केन्द्र नहीं होते हैं और खरीद नहीं होती है तो उससे किसान को परेशान होना पड़ता है और बाजार में माटी के मोल सारे सामानों को बेचना पड़ता है । अभी महोदया, कृषि मंत्री जी बैठे हैं । मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक बयान की तरफ । उन्होंने बयान में यह कहा है कि किसानों को ऋण की सुविधा हम वैसे ही देंगे जैसे स्टाक के आधार पर व्यापारियों को मिलता लेकिन इससे मामला हल होने वाला नहीं है क्योंकि किसान तो बेचारा गरीब है । उसमें अनुसूचित जाति के गरीब तथा अन्य गरीब लोग हैं इसलिये सरकार को अपना दृष्टिकोण साफ रखना चाहिए और दूसरी तरफ इनके दाम बढ़ाये जाने चाहिये । दूसरी बात यह है कि स्टेट खरीद केन्द्रों की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि किसानों का नुकसान न हो सके ।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों की तरफ से कृषि मंत्री श्री भजन लाल जी को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके कृषि मंत्री होने के बाद किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम अब की बार पिछले चार वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़े हैं . (**व्यवधान**) इनको जवाब देना जरूरी है । विरोधी पार्टी के नेता कह रहे थे कि बड़ी निराशा हुई है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : आप ही के जिले के हैं ।

श्री कल्पनाथ राय: एक बार इस देश में जनता पार्टी की हुकुमत आई, तीन साल तक, तो किसानों के खेतों में पैदा होने वाले

गेहूं का दाम ढाई रुपए क्विंटल बढ़ाया गया। ये मुख्य मंत्री थे तो किसानों को गन्ना जलाना पड़ा। इन्हीं के राज्य में ... (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव: हमने जो सुविधाएं किसानों को दी है यह सरकार कभी दे नहीं सकती है

श्री कल्पनाथ राय : तो जनता सरकार की हुकूमत के दौर में केवल ढाई रुपया क्विंटल गेहूं का दाम बढ़ाया गया जब चरण सिंह और मोरारजी देसाई यहां प्रधान मंत्री थे और जब ये मुख्य मंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना जलाया गया और तीन रुपए क्विंटल गन्ने का दाम था। तो कृपा करके तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। हमारे कृषि मंत्रियों और हमारी नीति के परिणामस्वरूप ही खाद्यान के मामले में देश आत्मनिर्भर है। किसानों के लिए हम लगातार दाम बढ़ाने की लड़ाई लड़ते हैं और सरकार ने अपने सीमित साधनों से ज्यादा अबकी बार देने का प्रयास किया है। इसलिए मैं सरकार के इस दाम बढ़ाये जाने की प्रशंसा करता हूं और भारत के करोड़ों किसानों की तरफ से भजन लालजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री राम नरेश यादव : महोदया, माननीय सदस्य ने कुछ आरोपों की बात की है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस समय खाद के दाम हमने प्रदेश में 54 रुपए और 70 रुपए किये थे। इन्होंने 112 रुपए किया था। महोदया, यही नहीं लगना माफ किया, सारा विकास कर समाप्त करके हमने किसानों को सुविधायें देने का काम किया और बिजली का रेट 15 रुपए .. (**व्यवधान**) .. से घटा कर 12 रुपए किया। इसलिए महोदय, जो जो सुविधायें हमारे समय में किसानों को मिली हैं वे कभी मिल नहीं सकती है... (**व्यवधान**)

श्री कल्प नाथ राय: आपके मुख्य मंत्रित्व काल में किसानों ने अपना गन्ना जलाया उत्तर प्रदेश के अंदर, हाहाकार मचा हुआ था.. किसानों की बड़ी दुर्गति हुई थी.. (**व्यवधान**) इनको लज्जा और शर्म आनी चाहिए कि इनके जमाने में किसानों का गन्ना जलाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर... (**व्यवधान**)

उपसभापति : कल्पनाथ जी आप भाषण नहीं दे रहे हैं आप बैठ जाइये... (**व्यवधान**)

श्री वीरेंद्र वर्मा : ये भी तो जनता पार्टी में थे भजन लाल जी।

श्री कल्पनाथ राय : हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं।

श्री गुलाम रसूल मट्टू : (जम्मू और कश्मीर) : मैडम डिप्टी चेयरमैन साहिबा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पहली बार इतने सालों में दस रुपए बढ़ाये गए। मगर मैं इसको दूसरी नुक्ते निगाह से देखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका क्या ख्याल है। सवाल यह है कि चावल की धान की कीमत उन्होंने 160 रुपए कर दी। और अंदाजा यह है कि धान को चावल में कन्वर्ट करने के लिए दो-तिहाई निकलता है। उसका मतलब है 160 रुपए उन्होंने मुकर्रर किया तो 2 रुपए 13 पैसे चावल उनको मिलेंगे। मगर मैं अभी लुधियाना में गया था कुछ दिन पहले तो खुले व्यापारी तीन रुपए में लेने के लिए तैयार थे। जो भी आदमी आ जाए हम तीन रुपए में लेंगे। मैं इसको इस रूप में और इस निगाह से देखना चाहता हूं कि अगर उनको व्यापारी तीन रुपए देने के लिए तैयार हैं तो माननीय मंत्री जी ने क्या उपाय किए हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जिसमें चावल की बहुत बड़ी जरूरत है सारे हिन्दुस्तान में जम्मू-काश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरल जो चावल खाने वाले प्रदेश हैं उनको अगर चावल नहीं मिले तो उन्होंने क्या उपाय किए हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उनको अपना टार्गेट मिल जाए जो कि मेरी नजर में 2 रुपए 13 पैसे हो जाता है, उनको तीन रुपए मिलते हैं तो वे व्यापारियों को ही बेचेंगे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं ?

†[شری غلام رسول مٹو (جموں اور کشمیر) : میڈم ڈپٹی چیئرمین

†Transliteration in Arabic Script.

श्री विश्वासराव रामराव पाटिल (महाराष्ट्र) उपसभापति महोदय, आज यह जो मंत्री महोदय ने प्राइसेज के बारे में बयान रखा है मुझे ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान से जिस तरीके से वह थट्टा कर रहे हैं बड़ी अटर हयूमिलिएशन कर रहे हैं वे गरीब लोग जो आवाज नहीं उठा सकते हैं इनके लिए अभी-अभी जो-जो प्राइस यहां रखे हैं या दिए गए हैं या फिक्स कर दिए गए हैं उसमें अब बाजार में जो प्राइस हैं वह तो उससे दुगने बढ़िया प्राइस बाजार में मिल सकते हैं। बात यह है कि अगर किसान की फसल एकदम बाजार में आए तो ऐसा होता है कि यह जो लोग यह जो नेफैड का कहा गया है वह कुछ खरीद नहीं पाता। लातूर में जो उससे भी कम प्राइस फिक्स कर दी थी लेकिन किसान अपना वह जो बिकने के लिए गया था बाजार में वह नैफेड नहीं ले सका, गवर्नमेंट नहीं ले सकी तो उनको तो सौ से भी कम कीमत मिल गई ऐसे ही होता रहता है और इसमें जो आयल सीड का सन् फ्लावर का कीमत बना दिया है 450 पर अभी सन-फ्लावर का कीमत 600 है। इसी तरह से यह तो किसानों और गरीबों को घाटा अपने बयान से किया है, इससे कोई भी अच्छा नहीं होगा। इससे कोई किसानों के लिए कोई अच्छा पैसा नहीं मिल सकता है।

उपसभापति : मुझे लगता है कि दो मैम्बर रह गए हैं एग्रीकल्चर की डिसकशन पर उनके पांच-पांच मिनट बोलने के बाद फिर आप इसका भी जवाब दे दीजिए।

श्री भजन लाल : सारा इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा।

उप सभापति : ठीक है, इकट्ठा ही जवाब दीजिए।

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE—contd

श्री कैलाशपति मिश्र (बिहार): उपसभापति महोदया, सब से पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस समय मुझे अवसर दिया। विषय का महत्व और बढ़ गया है, अभी एक साल पहले

صاحبہ - اسمیں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پہلے، پار اگلے سالوں میں دس روپئے بڑھائے گئے - مگر میں اسکو دوسرے نقطئہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں اور مانیئے منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انکا کیا خیال ہے - سوال یہ ہے کہ چاول کی دھان کی قیمت انہوں نے ۱۶۰ روپئے کودی - اور اندازہ یہ ہے کہ دھان کو چاول میں کنورٹ کرنے کیلئے دو تہائی نکلتا ہے - اسکا مطلب ہے کہ ۱۶۰ روپئے انہوں نے مقرر کیا تو دو روپئے تیرہ پیسے انہیں چاول انکو ملیگا - مگر میں ابھی لدھانہ میں گیا تھا کچھ دن پہلے تو کھلے بیوپاری تین روپئے دینے کیلئے تیار آھیں - تو مانئے منتری جی نے کیا اپائے کئے ھیں - کہ جو پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم ہے - اور جسمیں چاول کی بہت بڑی ضرورت ہے - سارے ہندوستان میں جموں کشمیر - ویسٹ بنگال اور کیرل جو چاول کھانے والے پردیش ھیں - انکو اگر چاول نہیں ملے تو انہوں نے کیا اپائے کئے ہے کہ پبلک ڈسٹری بیشن سسٹم میں انکو اپنا ٹارگیٹ مل جائے جو کہ میری نظر میں دو روپئے تیرہ پیسے ہو جاتا ہے انکو تین روپئے ملتے ھیں تو وہ بیوپاریوں کو ھی بیچیں گے اور پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم میں نہیں -]